FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ZORYA MASHPROEKT INDIA PRIVATE LIMITED

1.	Name of Corporate Person	Zorya Mashproekt India Private Limited
2.	Date of incorporation of Corporate Person	12th August, 2022
3.	Authority under which Corporate Person is incorporated /registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity Number ~~/ Limited Liability Identity Number~~ of Corporate Person	U34300DL2022PTC403135
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Person	IV-23/146 Lajpat Nagar IV, South Delhi, Delhi 110024, India.
6.	Liquidation Commencement Date of Corporate Person	02nd September, 2026
7.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Ms. Nayana Premji Savala Address: 1/101-A, Vishal Sushil CHS, Nariman Road, Vile Parle East, Mumbai 400057, Maharashtra, India Email: nalinisavala@gmail.com Tel.: 9082605500 IP Registration No: IBBI/IPA-003/IP-N00051/2017-18/10491 AFA Expires on 31/12/2027
8.	Last date for submission of claims	02nd October, 2026

Notice is hereby given that the Zorya Mashproekt India Private Limited has commenced voluntary liquidation on 02nd September, 2026.

The stakeholders of Zorya Mashproekt India Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 02nd October, 2026, to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of the Liquidator:

NAYANA PREMJI SAVALA
IBBI REG NO.
IBBI/IPA-003
IP-N00051
2017-18/10491
INSOLVENCY PROFESSIONAL

Nayana Premji Savala
Liquidator

Date: 03rd September, 2026
Place: Mumbai

मेरी दिल्ली

नई दिल्ली, शुक्रवार 4 सितंबर, 2026

www.jagatkranti.co.in

जगत क्रान्ति

दिल्ली में बनेगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम, सड़कें बार-बार खोदने की समस्या होगी समाप्त

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों की बार-बार खोदने को समाप्त के लिए मल्टी-यूटिलिटी डक्ट (एमयूडी) विकसित करेगी। इसके तहत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे, ताकि बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर-हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक यूटिलिटी सेवाओं के लिए इस उपयोग कर सकें। चांदनी चौक में इस पहल को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मल्टी-यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार-बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम हो जाएगी, यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी, नागरिकों को होने वाली असुविधा घटेगी और सड़कों की संरचनात्मक मजबूती को भी बेहतर ढंग से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार ने यह निर्णय हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास की हमारी सोच केवल आज की जरूरतों तक सीमित नहीं है। हम ऐसी आधारभूत संरचना तैयार करना चाहते हैं, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और टिकाऊ हो। मल्टी-यूटिलिटी डक्ट इसी सोच का हिस्सा है। इससे अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होगा और दिल्ली में भूमिगत यूटिलिटी नेटवर्क के विकास के लिए एक अधिक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार होगी। साझा भूमिगत कॉरिडोर उपलब्ध होने से यूटिलिटी नेटवर्क के रखरखाव और भविष्य में उनके विस्तार का काम भी अधिक आसान और तेज हो सकेगा। साथ ही खुदाई के दौरान यूटिलिटी लाइनों को होने वाले आकस्मिक नुकसान की आशंका कम करने और विभिन्न नागरिक एवं यूटिलिटी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति में डिस्कॉम, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। समिति की निगरानी और अनुशंसा के आधार पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में मल्टी-यूटिलिटी डक्ट के निर्माण और विस्तार से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मल्टी-यूटिलिटी डक्ट की तकनीकी डिजाइन में वेंटिलेशन, अग्नि-सुरक्षा, रखरखाव के लिए सुगम पहुंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न यूटिलिटी सेवाओं को एक साझा भूमिगत कॉरिडोर में सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महत्वपूर्ण पहल को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। इसके लिए चांदनी चौक में एस्प्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोर सराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से का चयन प्रस्तावित है। इन पर कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इन दोनों पायलट कॉरिडोर से प्राप्त अनुभव के आधार पर दिल्ली के अन्य हिस्सों में मल्टी-यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट से यह समझने में मदद मिलेगी कि विभिन्न यूटिलिटी सेवाओं को साझा भूमिगत व्यवस्था में किस प्रकार बेहतर ढंग से समायोजित किया जा सकता है और भविष्य में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की जरूरत के अनुसार ऐसी व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टी-यूटिलिटी डक्ट की पहल अलग-अलग एजेंसियों द्वारा अपनी-अपनी जरूरत के अनुसार किए जाने वाले बिखरे हुए भूमिगत कार्यों के बजाय समन्वित शहरी यूटिलिटी प्लानिंग की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है।

वोटरों के एसआईआर फॉर्म में मौजूद सभी जानकारियों के लिए बीएलए जिम्मेदार नहीं : हाई कोर्ट

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को केवल उसी जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसकी वे पुष्टि कर सकते हैं। बीएलए को वोटर के एन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म में मौजूद सभी जानकारियों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में निर्वाचन आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को निजी अंडरटेकिंग देनी जरुरी की गई है कि वे एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को वेरिफाई करते हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंदर यादव और दिल्ली कांग्रेस के

बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के लागू होने के पहले राजनीतिक दलों को 2002 के वोटर लिस्ट की प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी के अलावा फ्रोजन फोटो वोटर लिस्ट उपलब्ध करायी जाए।

याचिका में निर्वाचन आयोग के 24 जून, 2025 के दिशा-निर्देश की धारा 9(डी)(4) को चुनौती दी गई है जिसके तहत बूथ लेवल एजेंट को एन्यूमरेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी को निजी तौर पर वेरिफाई करते हुए अंडरटेकिंग देने को कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट से संबंधित सूचना का वेरिफिकेशन करना बूथ लेवल अफसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरों का एक वैधानिक कार्य है। इन कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों पर नहीं थोपा जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का आदेश जनप्रतिनिधित्व कानून के नियमों के अनुकूल नहीं है।

मुख्यमंत्री ने तेहखंड एटीएस का किया उद्घाटन, 50 ईवी बसों और दिल्ली-रेवाड़ी ई-बस सेवा को दिखाई झंडी

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को तेहखंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) का उद्घाटन किया। इसके साथ-साथ 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली-रेवाड़ी अंतरराज्यीय ई-बस सेवा और हसनपुर और गाजीपुर डिपो में दो नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्लीवासियों को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने इस एटीएस का नवंबर में ही शिलान्यास किया गया था, आज उसका उद्घाटन किया। उन्होंने कुछ ही महीनों में इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग की पूरी टीम और इससे जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साधुवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना ही हमारा संकल्प है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह उपस्थित रहे। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने तेहखंड डिपो में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, 50 नई इलेक्ट्रिक बसों, दो पब्लिक (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों (हसनपुर एवं गाजीपुर डिपो) तथा दिल्ली-रेवाड़ी अंतरराज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन नई सुविधाओं से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी के साथ-साथ दिल्लीवासियों को बेहतर और स्वच्छ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि एटीएस के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। इससे फिटनेस जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी सटीकता को बढ़ावा मिलेगा तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। वहीं, ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार से दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

स्वदेशी व्यापारी मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में स्वदेशी आंदोलन को मिली रफ्तार

बढ़ेगा स्वदेशी व्यापार तो स्वत: बढ़ेगा देश का मान : सुनील सिंघी

जगत क्रान्ति ⏭ विवेक भाटिया

नई दिल्ली : भारत में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग व उनके व्यापार को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्वदेशी व्यापारी मंच के तत्वाधान में मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें व्यापारियों का मार्गदर्शन मुख्य रूप से मंच के अ.भा. संगठक मा. कश्मीरी लाल, अ.भा. सह संगठक सतीश कुमार, व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के चेयरमैन सुनील सिंघी, स्वदेशी व्यापारी मंच के राष्ट्रीय संयोजक बी.सी. भरतिया, प्रवीण खण्डेलवाल (सांसद-चांदनी चौक) और राष्ट्रीय महामंत्री फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडल एवं सदस्य व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) आरके गौर का मिला। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश महामंत्री राजीव शर्मा सहित कई अन्य व्यापारी संगठनों के

गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

बैठक का शुभारंभ भारत माता, पं. दीनदयाल उपाध्याय जी, राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय ठेंगडी और भामा शाह जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुआ। इसमें 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा, बैठक में तय हुआ कि यह कोई नया संगठन नहीं, बल्कि सभी व्यापारिक संगठनों को एकजुट कर व्यापारी और राष्ट्र हित में आवाज उठाने वाला एक संयुक्त मंच होगा, जिसमें फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जैसे कई व्यापारिक संगठनों की सहभागिता रहेगी।

उल्लेखनीय है कि इस बैठक में आरके गौर को स्वदेशी व्यापारी मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राजीव शर्मा को दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। इस दौरान व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के चेयरमैन सुनील सिंघी ने सभी व्यापारियों से स्वदेशी व्यापार को बढ़ाने का संदेश देते हुए कहा कि बढ़ेगा स्वदेशी व्यापार तो स्वतः बढ़ेगा देश का मान।

मंच की राष्ट्रीय बैठक में निर्णय लिया गया कि मंच के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर टीम 21 और जिला स्तर पर टीम 11 (1 संयोजक, 2 सह संयोजक व जिला कार्यकारणी सदस्य-टीम 11 में एक महिला) का गठन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष 29 जून को भामाशाह जयंती पूरे देश में व्यापारी दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जीएसटी चोरी, मिलावट और नकली सामान बेचने वालों को मंच से नहीं जोड़ा जाएगा। केवल नैतिक व्यापार करने वालों को ही स्थान मिलेगा। छोटे व्यापारियों को बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरा जिला मेरा देश के तहत एक जिला एक उत्पाद व MSME योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों से समन्वय किया जाएगा। इस दौरान सरकार के स्वदेशी अभियान को गति देने हेतू स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने कों प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के अ. भा. सह संयोजक श्री अजय पतकी जी, स्वदेशी व्यापारी मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री संदीप बंसल जी, स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के चेयरमैन और इष्टब्रह्म श्री सतीश चावला जी , मध्य प्रदेश प्रभारी श्री राकेश द्विवेदी सहित प्रमुख कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मंच की यह बैठक नेहरू नगर भोपाल में 30 -31 अगस्त को आयोजित हुई।

दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत

नई दिल्ली, (हि.स.) : राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों की शर्त पर जमानत आदेश दिया है। कोर्ट ने 25 अगस्त को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि जैन की गिरफ्तारी केस दर्ज होने के 27 महीने बाद की गई, उन्हें सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस पर एसीबी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन आदतन अपराधी हैं। सत्येन्द्र जैन और दूसरे आरोपितों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने जैन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने कहा था कि जैन को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई जो उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। एसीबी ने सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया था। इन आरोपितों को एसीबी की उस एफआईआर के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो 11 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं 7, 7, 9, 13 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 42, 409, 418, 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं।

डीयू कुलपति ने पहले कार्बन गार्डन का किया उद्घाटन, लगाया कल्पवृक्ष का पौधा

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने गुरुवार को वनस्पति विज्ञान विभाग में देश के पहले कार्बन गार्डन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्बन गार्डन में एक कल्प वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि गार्डन का क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत ही अच्छी है। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में लगभग 17 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की समस्या लोगों के असंतुलित कार्यों से पैदा हुई है, उसका समाधान तकनीक से नहीं किया जा सकता उसके लिए दूसरे कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी को सतत समाधान का प्रयास करना होगा।

योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, अगर सही कदम नहीं उठाए तो यह दिल्ली प्रदूषण की राजधानी बन जाएगी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में भी कार्बन गार्डन की स्थापना की जाने की अपील की। कुलपति ने कहा कि भारत में पश्चिमी देशों का अंधानुसरण किया जाता है जिसके कारण से पर्यावरण की समस्या ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं बनाते हुए देश की पर्यावरणीय परिस्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए।

डीयू वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख एवं कार्बन गार्डन के संस्थापक प्रो. दीनबंधु साहू ने भारत के पहले कार्बन गार्डन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्बन गार्डन बढ़ते वायु प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण से निपटने का एक समाधान है। उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फुट के छोटे से इलाके में विकसित यह गार्डन भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाके के बीच एक मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क भी है। इस गार्डन में पौधों की 50 प्रजातियां हैं, जिनमें जड़ी-बूटियां, झाड़ियां और पेड़ शामिल हैं। इस अवसर पर कई विभागों के प्रमुखों सहित विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित काफी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: ओ-एसी-टी-126 से 129-26-27 (खुली), दिनांक 02.09.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएँ (खुली) आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम सं. 1, केस संख्या :** ओ-एसी-टी-126-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल में सुनायरा बिल्डिंग सहित ऑफिसर्स रेस्ट हाउस कैंपस की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 94,62,062.12, **बयाना राशि :** रु. 1,89,300/-, **क्रम सं. 2, केस संख्या :** ओ-एसी-टी-127-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल मंडल में तापसी-बाराबानी कॉर्ड के खंड में लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 05 एवं लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 10 के स्थान पर सीमित ऊँचाई के सबवे के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 11,42,49,763.17, **बयाना राशि :** रु. 22,85,000/-, **क्रम सं. 3, केस संख्या :** ओ-एसी-टी-128-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल मंडल में अण्डाल-सांईथिया, देवघर-दुमका, मोहनपुर-हंसडीहा खंड में 10000 से अधिक टीवीयू वाले लेवल क्रॉसिंग गेटों के इंटरलॉकिंग के लिए गेट बिल्डिंग, रिले हट के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 3,73,26,336.47, **बयाना राशि :** रु. 7,46,500/-, **क्रम सं. 4, केस संख्या :** ओ-एसी-टी-129-26-27, **कार्य का नाम:** आसनसोल मंडल में अण्डाल-बाराबानी और मधुपुर-गिरिडीह खंड में 10000 से अधिक टीवीयू वाले लेवल क्रॉसिंग गेटों के इंटरलॉकिंग के लिए गेट बिल्डिंग, रिले हट के प्रावधान के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 3,22,06,318.78, **बयाना राशि :** रु. 6,44,100/-, **कार्य की समापन अवधि:** 09 माह (क्रम सं. 1, 3 एवं 4 प्रत्येक हेतु) और 12 माह (क्रम सं. 2 हेतु)। **बंद होने की तिथि और समय:** 25.09.2026 को 12.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** में देखा जा सकता है।

ASN-242/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

उत्तर रेलवे

रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य कार्यशाला प्रबंधक कार्यालय, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत, उत्तर रेलवे निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा करते हैं।

1	निविदा संख्या	6S-Efile-317880R3Tender
2	कार्य का नाम और कार्य स्थान	"आरसीएनके/एसएनपी पर काम के दायरे के अनुसार एलएचबी कोच (पैंट्री कार) का नवीनीकरण)"
3	अनुमानित लागत	रुपये 3,58,84,115.80/- जीएसटी @ 18%सहित
4	बयाना राशि	रू. 7,17,700.00/–
5	निविदा फार्म का मूल्य	शून्य
6	कार्य अवधि	अवधि कार्य आरंभ होने से बारह महीने
7	निविदा प्रपत्र जमा करने की तथा खुलने की तिथि व समय	दिनांक 25/09/2026 खुलने का समय 15:00 बजे
8	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट साइट	उपरोक्त निविदा IREPS साईट पर उपलब्ध है जो कि है www.ireps.gov.in
9	यदि हिन्दी व इंग्लिश के नोटिस में कोई विरोधाभास है, तो इंग्लिश का नोटिस ही मान्य होगा।	

पत्र सं. 6S-Efile-317880R3Tender दिनांक 03/09/2026 3040/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

वैश्विक व्यवधान के बावजूद भारत की 7.8 फीसदी ग्रोथ शानदार : सीतारमण

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनियाभर में आई मुश्किलों के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। इसके साथ ही तमाम चुनौतियों के बावजूद यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 'एक्स' पर जारी पोस्ट में बताया कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को न्यूयॉर्क में बैंक ऑफ़ अमेरिका के साथ मिलकर भारत के महावाणिज्य दूतावास के द्वारा आयोजित एक उच्च-स्तरीय व्यावसायिक गोलमेज बैठक में निवेशकों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

निर्मला सीतारमण ने निवेशकों से कहा, दुनियाभर में आई मुश्किलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत ने 7.8 फीसदी की शानदार विकास दर दर्ज की है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सुधारों पर जोर देते हुए भारत ने कई सुधारों (जैसे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) के जरिए रेगुलेटरी निश्चितता भी प्रदान की है। ऐसे सुधारों से नियमों का पालन करना आसान हुआ है और कागजी काम कम हुआ है। उन्होंने बताया कि एक दशक से ज्यादा समय पहले सत्ता में आने के बाद से ही भारत सरकार का यह मुख्य फोकस रहा है।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, उनमें शामिल हैं : कैपिटल एसेट्स का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (खासकर एविएशन) के ज़रिए इंडस्ट्री को लगातार समर्थन देना; निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, एआई और डेटा सेंटर्स के विकास को बढ़ावा देना; ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को समर्थन देना, एमएसएमई को क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) को कम करना। उन्होंने कहा कि इन उपायों से बैंकों और इंडस्ट्री के फलने-फूलने, बढ़ने और मजबूत होने के लिए बेहतर बिजनेस माहौल बनाने में मदद मिली है।

सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 के आने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने लगातार आ रही चुनौतियों के बावजूद भारत पिछले कई वर्षों से फिस्कल प्रूडेंस (वित्तीय समझदारी) और फिस्कल डिसिप्लिन (वित्तीय अनुशासन) के रास्ते पर चलने के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने भारत में निवेश के माहौल के बारे में बात की, जिसमें काफी सुधार हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और उसे आसान बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी और प्रतिस्पर्धा दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने की बड़ी राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा हैं।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने स्वागत भाषण में कहा कि 31 अगस्त को जारी पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मजबूत संबंध बनाकर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का फ़ायदा दोनों देश उठा सकते हैं।

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम,२०१७ के विनियम १४ के तहत)

ज़ोर्या मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

१.	कॉरपोरेट व्यक्ति का नाम	ज़ोर्या मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
२.	कॉरपोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	१२ अगस्त, २०२२
३.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉरपोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली I
४.	कॉरपोरेट व्यक्ति का कॉरपोरेट पहचान संख्या / ~~सीमित दायित्व पहचान संख्या~~	U३४३००DL२०२२PTC४०३१३५
५.	कॉरपोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	IV-२३/१४६ लाजपत नगर IV, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली ११००२४, भारत।
६.	कॉरपोरेट व्यक्ति के परिसमापन शुरू होने की तिथि	०२ सितंबर, २०२६
७.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण नंबर	सुश्री नयना प्रेमजी सावला पता: १/१०१-A, विशाल सुशील सीएचएस, नरीमन रोड, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई ४०००५७, महाराष्ट्र, भारत ईमेल: nalinisavala@gmail.com दूरभाष : ९०८२६०५५०० IP पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-००३/IP-N०००५१/२०१७-१८/१०४९१ AFA की वैधता तिथि: ३१/१२/२०२७ तक
८.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	०२ अक्टूबर, २०२६

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ज़ोर्या मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ०२ सितंबर, २०२६ को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

ज़ोर्या मैशप्रोएक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ०२ अक्टूबर, २०२६ या उससे पहले, क्रम संख्या ७ के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक के समक्ष अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं। गलत या भ्रामक दावा प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर:

दिनांक: ०३ सितंबर, २०२६

स्थान: मुंबई

हस्ताक्षर/-

नयना प्रेमजी सावला

परिसमापक

Delhi Government unveils multi-tier strategy to tackle winter air pollution

Abhishek Byahut
TOP STORY NEWS

New Delhi: The Delhi government on Thursday announced a multi-tier enforcement strategy to combat air pollution during the upcoming winter season, with round-the-clock monitoring, targeted action in pollution hotspots and intensive ward-level supervision.

The announcement followed two high-level meetings, including a review chaired by Union Environment Minister Bhupender Yadav on the Delhi-NCR action plan for September 2026 to March 2027. Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said air pollution was a regional challenge requiring coordinated action by Delhi and neighbouring states.

For Delhi, 78 dedicated sub-divisional teams will be deployed across 39 sub-divisions. Led by AEE/JEE-level officers of the Delhi Pollution Control Committee, the teams will conduct inspections, including at night, to check biomass burning, construction dust, industrial pollution, use of unapproved fuels and illegal dumping. Another 256 ward-level monitoring teams will operate 24/7 across the capital, including 250 teams for MCD wards, four for NDMC areas and two for the Delhi Cantonment Board. They will monitor local pollution sources and facilitate action on complaints received through the Green Delhi and 311 apps.

The government will also intensify enforcement in 48 identified non-conforming pollution hotspots. District Magistrates will supervise action against unauthorised polluting industries involved in activities such as metal casting, powder coating, plastic waste reprocessing, spray painting and heat treatment.

Action will also target water-polluting industrial activities, including jeans dyeing, anodising, electroplating and phosphating.

Sirsa said the government's approach would be proactive and focused on grassroots enforcement, with departments directed to maintain strict vigilance and ensure swift action against violations throughout winter.

NDMC extends timings of 11 Public toilets in CP till midnight

TOP STORY NEWS

New Delhi: In a significant step towards providing better civic amenities and enhanced public convenience to citizens and visitors, the New Delhi Municipal Council (NDMC) has decided to extend the operating hours of 11 Public Toilet Utilities (PTUs) in Connaught Place up to midnight.

There are a total of 23 public toilets in Connaught Place, out of which 11 PTUs will, in the first instance, remain available to the public until midnight. The extended timings will come into effect from September 4, 2026.

Chairman, NDMC, Shri Manoj Kumar Dwivedi said that Connaught Place remains active and frequented by citizens, visitors and tourists till late hours. "Keeping in view the requirements of people who visit and stay in Connaught Place during the evening and late-night hours, NDMC has decided to extend the timings of 11 public toilets up to midnight from September 4 onwards. More public toilets will be brought under extended operating hours in due course," he said.

Out of total 23 Connaught Place, only 11 identified public toilet facilities will be available till midnight these are located at: S.B.S. Marg, Outer Circle, Connaught Place, Near E.S.S., Outer Circle, Connaught Place, Middle Circle, A Block, near RR-2, Middle Circle, K Block, between RR-4 & RR-5, Connaught Place, Middle Circle, E Block, between RR-7, Central Park, opposite D Block, Inner Circle, Connaught Place, Central Park, opposite F Block, Inner Circle, Connaught Place, Near Super Bazaar Parking, Outer Circle, Connaught Place, ECE House, Outer Circle, Connaught Place, Middle Circle, F Block, near RR-1, Panchkuian Road Chelmsford Road, Outer Circle, Connaught Place.

The NDMC has stated that the initiative to extend toilet timings in Connaught Place is aimed at ensuring that visitors and the general public have access to essential civic facilities during late evening and night hours. The Council will also examine extending the facility to additional public toilets in a phased manner based on feedback, public requirements and operational feasibility.

Delhi logs 34.9 deg C, AQI 'satisfactory'; rain likely on Fri, Sat

New Delhi: The national capital on Thursday recorded a maximum temperature of 34.9 degrees Celsius, 0.8 notches above the season average.

The minimum temperature was 27 degrees Celsius.

The India Meteorological Department (IMD) has predicted a generally cloudy sky with moderate rain on Friday and Saturday.

The air quality was recorded in the "satisfactory" category at 4 pm, with an Air Quality Index (AQI) reading of 74, Central Pollution Control Board (CPCB) data showed.

According to the CPCB, an AQI between zero and 50 is considered 'good', 51 to 100 'satisfactory', 101 to 200 'moderate', 201 to 300 'poor', 301 to 400 'very poor', and 401 to 500 'severe'.

Delhi Govt launches major green transport initiatives, adds 50 electric buses

Abhishek Byahut
TOP STORY NEWS

New Delhi: Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Thursday launched a series of initiatives aimed at making public transport cleaner, safer and more technology-driven, including a new Automated Testing Station (ATS), 50 electric buses, an interstate e-bus service and public EV charging facilities.

Gupta inaugurated Delhi's second ATS at the DTC's Tehkhand Depot. The four-lane facility will have an annual capacity to test 72,000 vehicles and will use automated systems to assess braking, suspension, headlight alignment, emissions and other fitness parameters.

The Chief Minister also flagged off 50 new 12-metre zero-emission electric buses, taking Delhi's fleet to around 6,840 buses, including 5,088 electric and 1,752 CNG buses. With this addition, Delhi now has the country's largest electric bus fleet. The government aims to expand the total fleet to around 14,000 buses by 2028-29.

Gupta inaugurated Delhi's second ATS at the DTC's Tehkhand Depot. The four-lane facility will have an annual capacity to test 72,000 vehicles and will use automated systems to assess braking, suspension, headlight alignment, emissions and other fitness parameters.

An interstate electric bus service between Dhaula Kuan and Rewari was also launched through Gurugram, Manesar and Dharuhera. The 86-km journey will cost Rs 153, with services operating from morning to evening.

Gupta also inaugurated public EV charging stations at DTC's Hasanpur and Ghazipur depots. Each station has four 240-kW chargers capable of serving commercial electric vehicles and cars. The Chief Minister said the government was focused on delivering solutions rather than merely discussing problems. She also announced plans to modernise old bus shelters and urged women to obtain Pink Cards for free bus travel before the September 17 deadline.

MCD announces chairpersons, vice-chairpersons of statutory, ad hoc committees

Abhishek Byahut
TOP STORY NEWS

New Delhi: The Municipal Corporation of Delhi (MCD) on Thursday has announced the chairpersons and vice-chairpersons of its statutory and ad hoc committees for 2026-27, with councillors from the BJP taking charge of several key panels.

The Education Committee will be headed by BJP councillor Yogesh Verma (Ward 64), while Amit Kharkhari (Ward 127) has been named Deputy Chairman.

Among the ad hoc committees, Neelam (Ward 214) has been appointed chairperson of the Remunerative Project Committee, with Ajay Ravi Hans (Ward 61) as vice-chairperson.

Ritesh Suji (Ward 224) will head the Licensing and Tehbazari Committee, while Shikha Bhardwaj (Ward 58) will serve as vice-chairperson. Suman Kumar Gupta (Ward 74) and Bobi (Ward 43) have been named chairperson and vice-chairperson, respectively, of the Community Services Committee.

Vikas (Ward 73) will chair the Welfare of Scheduled Castes Candidates Quota Committee, with Mamta (Ward 177) as vice-chairperson.

The Mahila Kalyan & Bal Vikas Committee will be headed by Rekha Rani (Ward 230), with Neela Kumari (Ward 38) as vice-chairperson. Neeta Bisht (Ward 247) and Manju Devi (Ward 180) will lead the Anti-Malaria Measures Committee as chairperson and vice-chairperson.

Ritu Goel (Ward 52) has been appointed chairperson of the Grievances Redressal Committee, while Rajesh Kumar Ladi (Ward 99) will be the vice-chairperson.

Standing Committee chairperson Satya Sharma will serve as ex-officio chairperson of both the High Powered Property Taxes Committee and the Municipal Accounts Committee. Renu Chaudhary (Ward 197) and Anuradha Sharma (Ward 122) will be their respective vice-chairpersons.

EASTERN RAILWAY

Open Tender Notice No.: 57-SDSTE-ASN-2026-27, dated: 02.09.2026. Sr. Divisional Signal & Telecom. Engineer, Eastern Railway, Asansol Division, Station Road, Asansol, Pin-713301 invites e-Tender for the following work. **Name of Work/ Location:** "Asansol Division - Provision of diagnostic terminal with analyzing software for Data Logger & MSDAC at stations/cabin." **Tender Value:** Rs. 1,71,02,563/-, **Earnest Money:** Rs. 3,42,100/-. **Completion period of the work:** 18 months from the date of issue of LOA. **Date and time of Closing of the tender:** 25.09.2026 at 14.00 hrs. **Website particulars: http:// www.ireps.gov.in.**

ASN-244/2026-27

Tender Notices are also available at Website www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in

Follow us at: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Central govt offices in Delhi to remain closed on Sep 11 for BRICS summit

New Delhi: All central government offices in the national capital will remain closed on September 11, in view of the BRICS summit, an official order issued on Thursday said.

BRICS Business Forum and 18th BRICS Leaders' Summit are scheduled to be held from September 11th to 13th at Bharat Mandalay here. The summit will be attended by leaders from about thirty BRICS members and partner countries, heads of international organisations and business representatives from BRICS nations including India, said the order issued by the Personnel Ministry.

BRICS Business Forum and 18th BRICS Leaders' Summit are scheduled to be held from September 11th to 13th at Bharat Mandalay here.

"Recognising the magnitude of this event, the substantial logistical arrangements involved and to minimise inconvenience to the general public, it has been decided to keep the central government offices located in Delhi/New Delhi closed on Friday, the 11th of September 2026 (12th and 13th of September 2026 being Saturday and Sunday respectively)," it said.

Malhotra says bail does not mean acquittal in Satyendar Jain case

Abhishek Byahut
TOP STORY NEWS

New Delhi: Delhi BJP president Harsh Malhotra on Thursday said the grant of bail to former Delhi minister Satyendar Jain did not amount to his acquittal, asserting that the case would now proceed to trial.

Reacting to Jain being granted bail in the alleged STP scam case, Malhotra said granting bail was part of the judicial process and should not be portrayed as a declaration of innocence.

"Getting bail is not a matter of 'Satyamev Jayate'," Malhotra said, adding that Jain would face trial and the investigating agency would seek his conviction.

Malhotra said an accused being sent to jail or granted bail was determined through the judicial process and that the same applied to Jain.

He alleged that the investigating agency had completed its investigation before arresting Jain and producing him before the court.

According to the statement, the court had sent Jain to jail on August 18/19 and granted him bail on Thursday.

The BJP leader also criticised the Aam Aadmi Party for treating the bail order as a political victory.

Malhotra maintained that the legal proceedings against Jain and other accused would continue and asserted that the investigating agency had a strong case.

He said the bail order should not be interpreted as a finding that the allegations against Jain had been disproved, stressing that the merits of the case would ultimately be examined during the trial.

WEST CENTRAL RAILWAY

Material Management Department

('e' Tender Notice for the supply of Stores, No.EPS/29/2026)

PCMM/WCR on behalf of the President of India invites the following advertised tenders through E-procurement System. No manual/postal offers shall be entertained. Tenders can be accessed under the link website https:/ireps.gov.in" for details and for submission of Tender.

Sr No.	Tender No.	Short Description	Tendered Qty.	Due Date
1	81256128	TWSEJ (ASSEMBLY) FOR THICK WEB SWITCH EXPANSION JOINT	100 Sets.	08/09/2026
2	81256278	DERAILING SWITCH: 1 in 8.5 OVER-RIDING DERAILING SWITCH (R.H.)	34 Sets.	09/09/2026
3	8125WCRTP-12A	COMPOSITE GROOVED RUBBER SOLE PLATE(CGRSP) FOR 60 KG.	2448758 Nos.	17/09/2026
4	8126WCRTP-08B	ELASTIC RAIL CLIP(ERC) J CLIP WITH HIGHER TOE	609880 Nos.	17/09/2026
5	20264026A	Set of Damper for WAG-9 locomotives	142 Sets.	21/09/2026
6	38262606	COMPLETE ASSEMBLY OF SWING DOOR (LH & RH)	893 Sets.	15/10/2026

" For tenders with estimated value below Rs. 50 lakh, interested firms are advised to visit www.ireps.gov.in"

(SD)
Principal Chief Material Manager, WCR, Jabalpur

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

Delhi, Assam Speakers discuss legislative modernisation, engage with students

TOP STORY NEWS

New Delhi: Delhi Legislative Assembly Speaker Vijender Gupta on Thursday met Assam Assembly Speaker Ranjeet Kumar Dass during the latter's visit to the Delhi Assembly. The two discussed legislative modernisation, sustainability, parliamentary heritage and possibilities for greater institutional cooperation.

The Speakers also interacted with Gen Z students of Keshav Mahavidyalaya under the Delhi Assembly's Youth Outreach Programme.

Gupta said young citizens must understand democratic institutions and participate in public life with awareness and responsibility. Dass described the students' visit as an opportunity to understand the functioning of a legislature and encouraged them to remain informed and engaged with democratic institutions.

The students were taken on a guided tour of the Assembly and shown the documentary "Vithal Bhai Ki Gaurav Gatha", highlighting the parliamentary legacy of Vithalbhai Patel.

The students were taken on a guided tour of the Assembly and shown the documentary "Vithal Bhai Ki Gaurav Gatha", highlighting the parliamentary legacy of Vithalbhai Patel.

Gupta briefed Dass on the Delhi Assembly's technology and sustainability initiatives, including its transition to paperless proceedings, efforts towards becoming fully solar-powered and "Vidhan Sāthi", an in-house AI-enabled platform providing legislative information to members.

The two leaders also discussed preservation of legislative heritage, including the proposed e-Sangrahalaya, museum and immersive light-and-sound experience. Gupta presented the coffee table book "Ek Shatabdi Yatra" and apprised Dass of the quarterly journal "Vidhan Chetna".

They agreed on exploring greater cooperation in legislative research, practices and knowledge sharing.

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ZORYA MASHPROEKT INDIA PRIVATE LIMITED

1.	Name of Corporate Person	Zorya Mashproekt India Private Limited
2.	Date of incorporation of Corporate Person	12th August, 2022
3.	Authority under which Corporate Person is incorporated /registered	Registrar of Companies, Delhi I
4.	Corporate Identity Number ~~/ Limited Liability Identity Number~~ of Corporate Person	U34300DL2022PTC403135
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Person	IV-23/146 Lajpat Nagar IV, South Delhi, Delhi 110024, India.
6.	Liquidation Commencement Date of Corporate Person	02nd September, 2026
7.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Ms. Nayana Premji Savala Address: 1/101-A, Vishal Sushil CHS, Nariman Road, Vile Parle East, Mumbai 400057, Maharashtra, India Email: nalinisavala@gmail.com Tel.: 9082605500 IP Registration No: IBBI/IPA-003/IP-N00051/2017-18/10491 AFA Expires on 31/12/2027
8.	Last date for submission of claims	02nd October, 2026

Notice is hereby given that the Zorya Mashproekt India Private Limited has commenced voluntary liquidation on 02nd September, 2026.

The stakeholders of Zorya Mashproekt India Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 02nd October, 2026, to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date : 03rd September, 2026
Place : Mumbai

Name and Signature of the Liquidator:
sd/-
Nayana Premji Savala
Liquidator